



# भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

पाँपुलेशन-स्केल डीपीआई के लिए ग्लोबल बेंचमार्क सेट करना

6 मार्च 2026

## प्रमुख बिंदु

- भारत ने 24 देशों के साथ डीपीआई कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं।
- यूपीआई अब 8 देशों में चालू है, जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सके।
- इंडिया स्टैक ग्लोबल, पार्टनर देशों को डीपीआई अपनाने में मदद करता है।
- भारत ने ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी में सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन दिए।

## परिचय

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) देशों के शासन करने, लेन-देन करने और सर्विस देने के तरीके को बदल रहा है। इस बदलाव में, भारत डिजिटल सिस्टम के बड़े यूज़र से बढ़कर आबादी के हिसाब से डिजिटल आर्किटेक्चर बनाने वाला बन गया है। भारत के नज़रिए की खासियत इसका स्केल, खुलापन और इंटीग्रेशन है। पहचान, पेमेंट और डेटा एक्सचेंज को इंटरऑपरेबल पब्लिक रेल के ज़रिए जोड़ा गया है जो वेलफेयर डिलीवरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और राज्य की क्षमता को सपोर्ट करते हैं। जैसे-जैसे दुनिया भर के देश भरोसेमंद और सबको साथ लेकर चलने वाले डिजिटल रास्ते खोज रहे हैं, भारत का अनुभव लगातार ध्यान खींच रहा है। यह मॉडल दिखाता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बंद प्लेटफॉर्म के बजाय एक पब्लिक गुड के तौर पर डिज़ाइन किया जा सकता है। यह दिखाता है कि सबको साथ लेकर चलना और कुशलता एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करके, भारत लगातार इस बात पर ग्लोबल बातचीत को आकार दे रहा है कि इक्कीसवीं सदी में डिजिटल सिस्टम कैसे बनाए और चलाए जाने चाहिए।

## ग्लोबल डिजिटल मोमेंट: डीपीआई क्यों ज़रूरी है?

आज इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़कों, बंदरगाहों और पावर ग्रिड तक सीमित नहीं है। यह डिजिटल है। यूनाइटेड नेशंस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी डिजिटल सिस्टम के एक सेट के तौर पर बताता है,

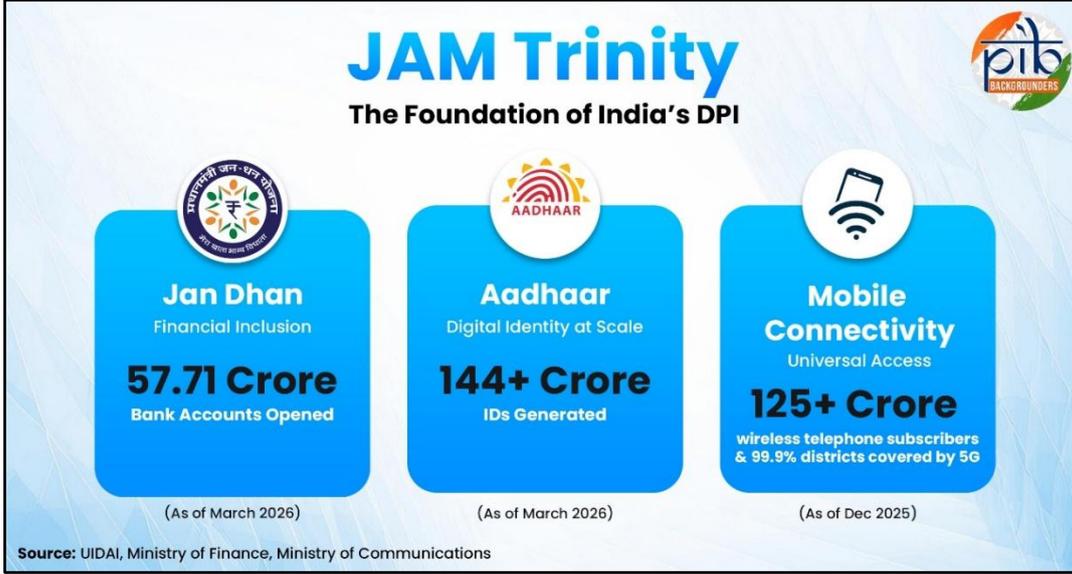
जो मॉडर्न समाज की रीढ़ हैं। ये सिस्टम लोगों, बिज़नेस और सरकारों के बीच सुरक्षित और बिना रुकावट के बातचीत को मुमकिन बनाते हैं। पहचान वेरिफाई करने और बैंक अकाउंट खोलने से लेकर तुरंत डिजिटल पेमेंट और सुरक्षित डेटा एक्सचेंज को मुमकिन बनाने तक, डीपीआई रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आकार देता है। जैसे रेलवे कभी इलाकों को मौकों से जोड़ता था, वैसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब यह तय करता है कि मॉडर्न इकॉनमी में कौन सर्विस, मार्केट और अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को फ़ायदा हो, इसके लिए यह ज़रूरी है कि वह सबको साथ लेकर चलने वाला, आपस में काम करने वाला और लोगों के हित में चलने वाला हो। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया डिजिटल आइडेंटिफ़िकेशन सिस्टम सब्सिडी डिलीवरी, वोटर रजिस्ट्रेशन और सुरक्षित बैंकिंग में मदद कर सकता है। जब इसे पेमेंट और डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क से जोड़ा जाता है, तो यह एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाता है जो राज्य की क्षमता को मज़बूत करता है और मौके बढ़ाता है।

इस बैकग्राउंड में, भारत का अनुभव इस बात का एक काम करने वाला उदाहरण है कि बड़े पैमाने पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हासिल कर सकता है। भारत ने बहुत कम लागत पर 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोगों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। यह एक खुला और आसानी से मिलने वाला नेटवर्क है, जिसे रेगुलेशन और कई तरह के एप्लिकेशन का सपोर्ट है जो इकॉनमी को मॉडर्न बनाते हैं, गवर्नेंस में सुधार करते हैं और ज़िंदगी बदलते हैं। भारत के मामले में, सबको साथ लेकर चलना, इनोवेशन और भरोसे के सिद्धांत इसके डीपीआई इकोसिस्टम की ऑपरेशनल सच्चाई हैं। बड़े पैमाने पर, और मापने लायक असर के साथ, भारत ने दिखाया है कि डिजिटल सिस्टम विकास को तेज़ करते हुए डेमोक्रेसी को और मज़बूत कर सकते हैं।

## भारत के डीपीआई की नींव: जैम ट्रिनिटी

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रातों-रात नहीं बना। इसे पहचान, बैंकिंग और कनेक्टिविटी के सोचे-समझे मेल से बनाया गया था। इस मेल ने जैम ट्रिनिटी का रूप लिया। जन धन बैंक अकाउंट, आधार एनरोलमेंट और बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन की पहुंच ने भारत के डिजिटल बदलाव के लिए बेस लेयर बनाया। इन सबने मिलकर लोगों को सीधे और वेरिफाई किए जा सकने वाले तरीके से सरकार से जोड़ा। जैम के ज़रिए, वेलफेयर बेनिफिट सीधे बैंक अकाउंट में जाने लगे। बिचौलिए कम हो गए। देरी कम हो गई। लीकेज कम हो गया। इस इंटीग्रेशन के पैमाने ने उस चीज़ की नींव रखी जो बाद में एक बड़े DPI इकोसिस्टम में बदली।



## आधार

आधार ने देश भर के लोगों के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पेश किया। इसने अच्छी सर्विस डिलीवरी के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन और सिंक्योर ऑथेंटिकेशन को मुमकिन बनाया। मार्च 2026 तक, 144 करोड़ से ज़्यादा आधार नंबर जनरेट किए जा चुके थे। इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा के सिस्टम में गहराई से इंटीग्रेशन दिखाता है। अकेले 2024-25 में, 2,707 करोड़ से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन ट्रांज़ैक्शन किए गए। आइडेंटिटी पोर्टेबल हो गई। वेरिफिकेशन लगभग तुरंत हो गया। सर्विस तक एक्सेस ज़्यादा भरोसेमंद और ट्रांसपैरेंट हो गई।

## जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इन्क्लूजन के तौर पर शुरू किया गया था, का मकसद भारत में हर उस वयस्क को बैंक अकाउंट, एक फाइनेंशियल पहचान और क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच देना था, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। अगस्त 2014 में शुरू हुई यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्क्लूजन पहलों में से एक बन गई। अकाउंट्स की संख्या 2015 में 14.72 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 तक 57.71 करोड़ हो गई। डिपॉजिट मार्च 2015 में ₹15,670 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 तक ₹2.94 लाख करोड़ हो गया। कुल 39.98 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड लाभार्थियों को जारी किए गए। वित्तीय भागीदारी बढ़ी। सेविंग्स फॉर्मल सिस्टम में आई जिससे इकोनॉमिक एजेंसी मजबूत हुई।

## मोबाइल फ़ोन और कनेक्टिविटी

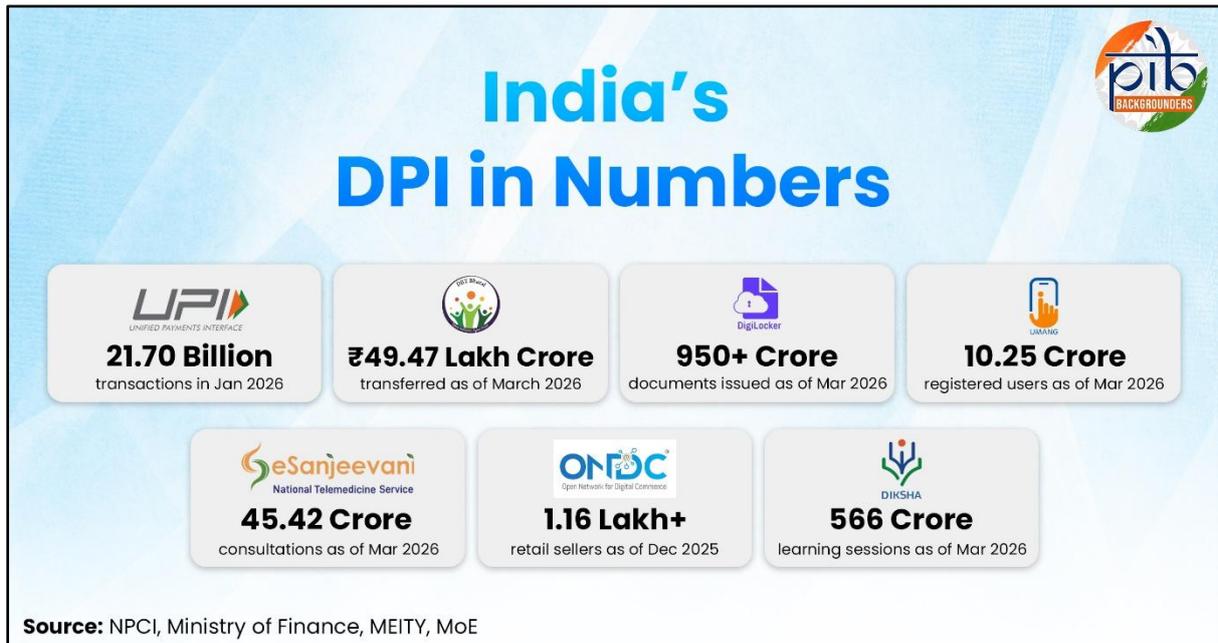
कनेक्टिविटी ने ट्रायंगल को पूरा किया। 85.5 प्रतिशत भारतीय घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन होने के साथ, मोबाइल फ़ोन एक बैंक, एक क्लासरूम और पब्लिक सर्विस का गेटवे बन गया। दिसंबर 2025

के आखिर तक वायरलेस टेलीफोन सब्सक्राइबर की संख्या 125.87 करोड़ तक पहुँच गई। पाँचवीं जेनरेशन (5G) मोबाइल सर्विस अब 99.9 प्रतिशत ज़िलों में उपलब्ध हैं, जो 85 प्रतिशत आबादी को कवर करती हैं। दिसंबर 2025 तक, पूरे देश में 5.18 लाख 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन लगाए जा चुके थे। इस बड़ी डिजिटल पहुँच ने यह पक्का किया कि पहचान और बैंकिंग सिर्फ शहरी सेंटर तक ही सीमित न रहें। वे ग्रामीण और शहरी भारत में समान रूप से एक्सेसिबल हो गए।

JAM ट्रिनिटी ने वह बुनियादी रेल बनाई जिस पर भारत का बड़ा DPI इकोसिस्टम बना, जिसने पहचान, फ़ाइनेंस और कनेक्टिविटी को पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर जोड़ा।

## भारत के डिजिटल सूचना प्रणाली (डीपीआई स्टैक) का उदय

भारत का डीपीआई स्टैक कुछ मूलभूत डिजिटल प्रणालियों से विकसित होकर एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा बन गया है, जो ओपन एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) और सार्वजनिक डिजिटल वस्तुओं पर आधारित है। इसे इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है, जो जनसंख्या स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान के मूलभूत तत्वों को सुलभ बनाता है। डिजिटल पहचान और वित्तीय समावेशन से शुरू हुआ यह ढांचा धीरे-धीरे भुगतान, कल्याणकारी वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और शासन प्लेटफार्मों तक विस्तारित हुआ। ये प्रणालियाँ परस्पर संचालित डिजिटल रेल के माध्यम से एक साथ काम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसका परिणाम केवल अलग-अलग पोर्टलों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक एकीकृत डिजिटल आधार है जो आर्थिक गतिविधियों और सार्वजनिक सेवा वितरण को समर्थन देता है। यद्यपि इसे भारत के संदर्भ में विकसित किया गया है, यह मॉडल मॉड्यूलर और अनुकूलनीय है, जो इसे राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रासंगिक बनाता है।



## डिजिटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने रिटेल पेमेंट्स को एक आसान डिजिटल एक्सपीरियंस में बदल दिया है। यह रियल टाइम में लोगों और मर्चेन्ट्स के बीच तुरंत, इंटरऑपरेबल और सुरक्षित ट्रांज़ैक्शन को मुमकिन बनाता है। जनवरी 2026 में, इसने ₹28.33 लाख करोड़ से ज़्यादा के 21.70 बिलियन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए, जो रोज़ाना के कॉमर्स में इसके गहरे इंटीग्रेशन को दिखाता है। कुल 691 बैंक UPI प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, जो इसके बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशनल अपनाने को दिखाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, बढ़ते रिटेल डिजिटल पेमेंट्स पर अपनी जून 2025 की रिपोर्ट में, ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना। प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम नाम की 2024 एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का लगभग 49 प्रतिशत UPI का है। भारत में, कुल रिटेल पेमेंट ट्रांज़ैक्शन का 81 प्रतिशत यूपीआई रेल पर प्रोसेस होता है, जिससे यह पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेन्ट पेमेंट्स के लिए पसंदीदा तरीका बन गया है।
- **पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS):** PFMS ने सरकारी खर्च में ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल को मज़बूत किया है। यह एक वेब बेस्ड ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन सिस्टम है जो सरकारी फंड की एंड-टू-एंड मॉनिटरिंग और लागू करने वाली एजेंसियों और बेनिफिशियरी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने में मदद करता है। दिसंबर 2014 में, इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पेमेंट, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी कर दिया गया था। इस सुधार से डुप्लीकेट और नकली बेनिफिशियरी हटाने और लीकेज कम करने में मदद मिली। नतीजतन, सरकार ने 2015 और मार्च 2024 के बीच ₹4.31 लाख करोड़ से ज़्यादा बचाए। जनवरी 2026 तक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए ट्रांसफर की गई कुल रकम ₹49.09 लाख करोड़ को पार कर गई है, जो टारगेटेड और अकाउंटेबल वेलफेयर डिलीवरी की ओर बदलाव का संकेत है। व्यक्ति से व्यापारी को पेमेंट।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** 2022 में लॉन्च हुआ ONDC एक ओपन नेटवर्क है जिसे डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह खरीदारों और विक्रेताओं को एक ही मार्केटप्लेस के बजाय इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म के ज़रिए जोड़ता है। यह मार्केट एक्सेस को बढ़ाता है, एंट्री की रुकावटों को कम करता है और



खासकर छोटे बिज़नेस के लिए ज़्यादा भागीदारी को मुमकिन बनाता है। दिसंबर 2025 तक, भारत भर के 630+ शहरों और कस्बों से ONDC पर कुल 1.16 लाख+ रिटेल विक्रेता लाइव हैं।

- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस:** गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट को डिजिटाइज़ किया है और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भागीदारी को बढ़ाया है। यह सरकारी संस्थाओं द्वारा सामान और सर्विस की ट्रांसपेरेंट और कुशल प्रोक्योरमेंट के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है। नवंबर



2025 तक, लगभग 3.27 करोड़ ऑर्डर प्रोसेस किए जा चुके थे, जिनकी कुल ग्रॉस मर्चेडाइज़ वैल्यू ₹16.41 लाख करोड़ से ज़्यादा थी, जिसमें सर्विस में ₹7.94 लाख करोड़ और प्रोडक्ट में ₹8.47 लाख करोड़ शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म 10,894 से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी और 348 सर्विस कैटेगरी को सपोर्ट करता है, जिसमें 1.67 लाख से ज़्यादा बायर

ऑर्गनाइज़ेशन शामिल हैं। 24 लाख से ज़्यादा सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी प्रोफाइल पूरी कर ली है, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ शामिल हैं, जो कुल ऑर्डर वैल्यू का 44.8 प्रतिशत हिस्सा देते हैं और उन्हें ₹7.35 लाख करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर मिले हैं।

## सिटीज़न सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म

- **डिजिलॉकर:** 2015 में लॉन्च हुआ डिजिलॉकर, नागरिकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट लेकर आया। यह लोगों को सहमति के आधार पर ऑथेंटिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्टोर करने, एक्सेस करने और



शेयर करने की सुविधा देता है। यह प्लेटफॉर्म ऑथेंटिसिटी पक्का करता है और नकली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कम करता है। नागरिक कभी भी और कहीं से भी ज़रूरी लाइफ़लाइंग रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। 5 मार्च 2026 तक, DigiLocker के 67.63 करोड़ यूज़र थे। मार्च 2026 तक, प्लेटफॉर्म के ज़रिए 950 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जारी किए जा चुके थे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है।

- **उमंग:** 2017 में लॉन्च हुआ उमंग, या यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस,



भारत में मोबाइल गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की सर्विसेज़ को

एक्सेस करने के लिए सिंगल विंडो मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म देता है। नागरिक EPFO बैलेंस और क्लेम, पैन और आधार सर्विसेज़, डिजिलॉकर एक्सेस, यूटिलिटी बिल पेमेंट, पेंशन सर्विसेज़, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, पासपोर्ट से जुड़ी सर्विसेज़, ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज़, एग्जाम रिजल्ट वगैरह जैसी सर्विसेज़ को एक्सेस करने के लिए उमंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मार्च 2026 तक, इसमें 10.25 करोड़ यूजर रजिस्ट्रेशन और 723.36 करोड़ ट्रांज़ेक्शन रिकॉर्ड किए गए। पोर्टल पर 2,400 से ज़्यादा सरकारी सर्विसेज़ उपलब्ध हैं, जो इसे नागरिकों और स्टेट के बीच एक अहम इंटरफ़ेस बनाती हैं।

- **ई-कोर्ट्स:** ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ

एंड जस्टिस के तहत एक पैन इंडिया मिशन मोड इनिशिएटिव है।

इसका मकसद इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) के

इस्तेमाल से ज्यूडिशियल प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपैरेंट और

एक्सेसिबल बनाना है। 2011 से 2015 तक फेज़ I में बेसिक

कंप्यूटराइजेशन और इंटरनल कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया। इसके

चलते, 14,249 कोर्ट कंप्यूटराइज्ड किए गए और 13,683 कोर्ट में लोकल एरिया नेटवर्क इंस्टॉल

किए गए। 2015 से 2023 तक फेज़ II में नागरिकों के लिए ICT इनेबल्ड सर्विस डिलीवरी की

ओर शिफ्ट किया गया। इसमें वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्टैकहोल्डर ट्रेनिंग, ई-सेवा

केंद्र, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ और तालुका लीगल कमेटियों का कंप्यूटराइजेशन

शुरू किया गया। एडवांस्ड केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड

और डिजिटल फाइलिंग और ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम ने ज्यूडिशियल सर्विसेज़ तक लोगों

की पहुंच को बदल दिया।

सितंबर 2023 में, यूनियन कैबिनेट ने 2023 से 2027 के समय के लिए ₹7,210 करोड़ के

खर्च के साथ फेज़ III को मंजूरी दी। यह फेज़ डिजिटल और पेपरलेस कोर्ट को आगे बढ़ाता है

और पुराने रिकॉर्ड और पेंडिंग केस को पूरी तरह से डिजिटाइज़ करता है। यह कोर्ट, जेल और

हॉस्पिटल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बढ़ाता है और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से आगे

बढ़कर ऑनलाइन कोर्ट का दायरा बढ़ाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्टिकल कैरेक्टर

रिकग्निशन जैसी नई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन केस पेंडेंसी एनालिसिस और लिटिगेशन ट्रेंड के

अनुमान में मदद करता है। यह पहल डेटा इनेबल्ड ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर एक

स्ट्रक्चरल बदलाव को दिखाता है।



**हेल्थ और न्यूट्रिशन इकोसिस्टम**

- **कोविन:** 16 जनवरी 2021 को, CoWIN को भारत के COVID 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के डिजिटल बैकबोन के तौर पर लॉन्च किया गया था। इसने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के वैक्सीन बनाने वालों, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हेल्थकेयर वर्कर्स और बेनिफिशियरीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा। 220 करोड़ से ज़्यादा डोज़ मैनेज करके, CoWIN ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में से एक में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाई। रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग ने कोऑर्डिनेशन और पब्लिक ट्रस्ट को बेहतर बनाया। इसके डिज़ाइन और एग्ज़िक्यूशन ने इंटरनेशनल लेवल पर दिलचस्पी दिखाई है, कई देशों ने इसे डिजिटल पब्लिक हेल्थ सिस्टम के मॉडल के तौर पर देखा है।



- **ई-संजीवनी:** नवंबर 2019 में लॉन्च हुई ई-संजीवनी ने टेलीमेडिसिन के ज़रिए हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाई। यह दूर के डॉक्टर से मरीज़ों को सलाह देने में मदद करता है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। यह प्लेटफॉर्म दूर के समुदायों को स्पेशलिस्ट सलाह देते हुए आने-जाने का खर्च और इंतज़ार का समय कम करता है। 5 मार्च 2026 तक, इसने 45.42 करोड़ मरीज़ों को सेवा दी है और 2.3 लाख हेल्थकेयर प्रोवाइडर को जोड़ा है। टेलीकंसल्टेशन पायलट से मेनस्ट्रीम पब्लिक हेल्थ सर्विस बन गई है।



- **ई-हॉस्पिटल और ओआरएस:** डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के तौर पर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने ई-हॉस्पिटल, ई-ब्लडबैंक और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया। ORS पोर्टल 1 जुलाई 2015 को हॉस्पिटल की सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच देने के लिए लॉन्च किया गया था। ई-हॉस्पिटल एप्लिकेशन एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तौर पर काम करता है जो अंदरूनी वर्कफ़्लो, अपॉइंटमेंट, डायग्नोस्टिक्स और बिलिंग को डिजिटलाइज़ करता है। यह क्लाउड-बेस्ड सर्विस मॉडल के ज़रिए सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनॉमस और कोऑपरेटिव हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध है। ई-ब्लडबैंक एप्लिकेशन एंड टू एंड ब्लड बैंक मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। ये सिस्टम मिलकर मरीज़ों, हॉस्पिटल और डॉक्टरों को एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ते हैं और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के साथ सेवाओं को इंटीग्रेट करते हैं।



- **आरोग्य सेतु:** 2 अप्रैल 2020 को, COVID 19 को फैलने से रोकने की कोशिशों में मदद के लिए आरोग्य सेतु लॉन्च किया गया था। इसने ब्लूटूथ बेस्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हॉटस्पॉट मैपिंग और हेल्थ एडवाइज़री को फैलाने में मदद की। यह एप्लीकेशन तब से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से चलने वाला एक नेशनल हेल्थ ऐप बन गया है। यूज़र्स



**Aarogya Setu**

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और वेरिफाइड प्रोवाइडर्स से डिजिटल लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस देख सकते हैं। यह ई संजीवनी ओपीडी सर्विस के ज़रिए ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन शेड्यूल करने की भी सुविधा देता है, जिससे देखभाल की कंटिन्यूटी मज़बूत होती है।

- **नेशनल नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज़ प्लेटफॉर्म (NCD):** नेशनल नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज़



प्लेटफॉर्म मुख्य लाइफस्टाइल बीमारियों की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में मदद करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और टाटा ट्रस्ट्स के साथ मिलकर बनाया गया, यह आबादी के आधार पर स्क्रीनिंग और लंबे समय तक बीमारी के मैनेजमेंट में मदद करता है। दिसंबर 2025 तक, 74.97 करोड़ बेनिफिशियरी इस सिस्टम में एनरोल हो

चुके थे। 8.64 करोड़ से ज्यादा मरीज़ हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है, जिससे ज्यादा रिस्क वाली आबादी की सिस्टमैटिक ट्रेकिंग हो पाती है।

- **पोषण ट्रेकर:** महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 मार्च 2021 को नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न के ज़रिए पोषण ट्रेकर शुरू किया था। यह न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग के लिए एक गवर्नेंस टूल का काम करता है। यह बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वज़न की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह न्यूट्रिशन सर्विस डिलीवरी की लास्ट माइल ट्रेकिंग भी करता है। जनवरी 2026 तक, 14.03 लाख



**Poshan Tracker**

आंगनवाड़ी सेंटर इस सिस्टम से जुड़ चुके थे और 8.90 करोड़ योग्य लाभार्थी इस सिस्टम पर रजिस्टर्ड थे, जिससे डेटा पर आधारित न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को मज़बूती मिली।

## शिक्षा और कौशल

- **दीक्षा:** 2017 में लॉन्च हुआ दीक्षा, स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म है। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की एक पहल है।



इस प्लेटफॉर्म को लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ सीबीएसई समेत सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ और बोर्ड्स ने अपनाया है। दीक्षा का मकसद एक ऐसा लर्निंग इकोसिस्टम बनाना है जो इक्कीसवीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करे। एजुकेशन को आसान, दिलचस्प और हर सीखने वाले के हिसाब से बनाया गया है। यह क्लासरूम से आगे तक फैला हुआ है और टीचर्स, स्टूडेंट्स

और एडमिनिस्ट्रेटर्स सभी को सपोर्ट करता है। 5 मार्च 2026 तक, प्लेटफॉर्म के ज़रिए 566 करोड़ लर्निंग सेशन दिए जा चुके थे। इसके 2.11 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। कोर्स एनरोलमेंट 18.52 करोड़ हैं, जिसमें 14.71 करोड़ कोर्स पूरे हो चुके हैं और 12.69 करोड़ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।

- **स्किल इंडिया डिजिटल हब:** 2023 में लॉन्च किया गया, स्किल इंडिया डिजिटल हब एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में मदद करने के लिए बनाया गया था। यह ऑनलाइन ट्रेनिंग को API के ज़रिए दिए जाने वाले भरोसेमंद स्किल क्रेडेंशियल्स के साथ-साथ पेमेंट और जॉब डिस्कवरी लेयर्स के साथ जोड़ता है। अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म उद्यम, ई-श्रम, नेशनल करियर सर्विस और ASEEM पोर्टल्स को इंटीग्रेट करता है ताकि सरकार से नागरिक, बिज़नेस से नागरिक और बिज़नेस से बिज़नेस सर्विसेज़ मिल सकें। यह लर्नर्स को एम्प्लॉयर्स से जोड़ता है और इंडस्ट्री की डिमांड के साथ ट्रेनिंग को अलाइन करने में मदद करता है। एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन उभरती वर्कफोर्स की ज़रूरतों के आधार पर करिकुलम को बदल सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिससे भारत का ह्यूमन कैपिटल इकोसिस्टम मज़बूत होता है।



### गवर्नेंस कैपेसिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए डिजिटल सिस्टम

- **ई-ऑफिस:** ई-ऑफिस ने सरकारी डिपार्टमेंट में पेपरलेस कामकाज को मुमकिन बनाया है। यह इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट और डिजिटल फैसले लेने में मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद एक आसान, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपैरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना है। ओपन आर्किटेक्चर पर बना, इसे सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक यूनिफाइड डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर इंडिपेंडेंट फंक्शन को जोड़ता है, जिससे एफिशिएंसी बेहतर होती है और प्रोसेस में होने वाली देरी कम होती है।
- **API सेतु:** MeitY ने मार्च 2020 में API सेतु शुरू किया, जिसे ओपन API प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के ज़रिए सरकारी डेटा और सर्विसेज़ को सुरक्षित और स्टैंडर्ड तरीके से शेयर करने में मदद करता है। यह प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग से लेकर कंजम्प्शन तक पूरे API लाइफसाइकल को मैनेज करता है और पब्लिक और प्राइवेट दोनों इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। मार्च 2026 तक, प्लेटफॉर्म पर अभी 8,036 API हैं, जिसमें 6,592 कंज्यूमर, 2,559



API Setu

पब्लिशर और 10,530 ऑर्गनाइजेशन शामिल हैं। स्ट्रक्चर्ड और सुरक्षित डेटा एक्सचेंज को आसान बनाकर, API सेतु भारत के डिजिटल गवर्नेंस लैंडस्केप में इंटरऑपरेबिलिटी और इनोवेशन को मज़बूत करता है।

- **पीएम गतिशक्ति:** 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन के लिए



एक जीआईएस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है। इसका मकसद इकोनॉमिक ज़ोन में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को इनेबल करना और मिनिस्ट्रीज़ और एजेंसियों के बीच सिंक्रोनाइजेशन को बेहतर बनाना है। इस फ्रेमवर्क के तहत

बनाया गया नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, मल्टीमॉडलिटी, इंटरमॉडलिटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और डेटा ड्रिवन डिजीजन मेकिंग को पक्का करने के लिए प्लानिंग स्टेज पर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन करता है। 10 फरवरी, 2026 तक, इस मैकेनिज्म के ज़रिए ₹16.10 लाख करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाले 352 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन किया गया है। इनमें से 201 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है और 167 पर काम चल रहा है। यह प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस में तालमेल और ट्रांसपेरेंसी लाता है।

ये इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म मिलकर दिखाते हैं कि कैसे भारत का DPI स्टैक एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल बैकबोन के रूप में डेवलप हुआ है जो बड़े पैमाने पर गवर्नेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ और सिटिज़न एम्पावरमेंट को पावर दे रहा है।

## भारत की डीपीआई डिप्लोमेसी

डीपीआई पर भारत का जुड़ाव एक गहरी सभ्यतागत सोच से आता है। वसुधैव कुटुम्बकम् का मतलब है कि दुनिया एक परिवार है। यह एक ऐसा नज़रिया दिखाता है जो सीमाओं, भाषाओं और विचारधाराओं से परे मिलकर तरक्की करने को बढ़ावा देता है। डिजिटल युग में, डीपीआई पर भारत के जुड़ाव के ज़रिए इस सोच को नई पहचान मिली है। टेक्नोलॉजी को एक बंद संपत्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी पब्लिक गुड के तौर पर देखा जाता है जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास में मदद कर सकती है। भारत न सिर्फ़ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को इसे अपने हिसाब से डेवलप करने और अपनाने में भी मदद कर रहा है। जैसे-जैसे देश भरोसेमंद डिजिटल रास्ते खोज रहे हैं, भारत का अनुभव लगातार ग्लोबल पॉलिसी बातचीत में शामिल हो रहा है। नीचे दी गई कोशिशें दिखाती हैं कि यह तरीका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे लागू हो रहा है।

निम्नलिखित पहलें दर्शाती हैं कि इस दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे लागू किया जा रहा है:

## डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप

फरवरी 2026 तक, भारत सरकार ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग के लिए 24 देशों के साथ मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) और एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये पार्टनरशिप टेक्निकल जानकारी शेयर करने और डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को कॉपी करने में मदद करने पर फोकस करती हैं। सहयोग के एरिया में डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल पेमेंट, डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क और सर्विस डिलीवरी सिस्टम शामिल हैं। इसका मकसद किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पर सहयोग करना है। इस जुड़ाव ने भारत को उन देशों के लिए एक प्रैक्टिकल पार्टनर के तौर पर खड़ा किया है जो आबादी के हिसाब से डिजिटल सिस्टम बनाना चाहते हैं।

क्र.सं.	इंडिया स्टैक / डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एमओयू वाले देश
1	रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया
2	रिपब्लिक ऑफ सिएरा लियोन
3	रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम
4	एंटीगुआ और बारबुडा
5	पापुआ न्यू गिनी
6	रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो
7	यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया
8	रिपब्लिक ऑफ केन्या
9	रिपब्लिक ऑफ क्यूबा
10	रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया
11	लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
12	सेंट किट्स एंड नेविस
13	इथियोपिया
14	जमैका
15	गाम्बिया
16	फिजी
17	गुयाना

18	वेनेजुएला
19	श्रीलंका
20	ब्राज़ील
21	लेसोथो
22	मालदीव
23	मंगोलिया
24	मलेशिया

## यूपीआई का क्रॉस बॉर्डर विस्तार

भारत का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देश की सीमाओं को पार कर चुका है। यूपीआई अब यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर समेत 8 देशों में लाइव है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर अपनाने से रेमिटेंस आसान हो रहा है, पेमेंट एफिशिएंसी बेहतर हो रही है और फाइनेंशियल इनक्लूजन बढ़ रहा है। बिना किसी रुकावट के क्रॉस बॉर्डर



ट्रांजैक्शन को मुमकिन बनाकर, UPI ने ग्लोबल फिनटेक लैंडस्केप में भारत की मौजूदगी को मजबूत किया है। सिस्टम के स्केल और रिलायबिलिटी ने दुनिया भर के पॉलिसीमेकर्स और रेगुलेटर्स का ध्यान खींचा है।

## इंडिया स्टैक ग्लोबल

एक स्ट्रक्चर्ड सहयोग को आसान बनाने के लिए, इंडिया स्टैक ग्लोबल को एक खास प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया था ताकि भारत के DPI सॉल्यूशन दिखाए जा सकें और पार्टनर देशों को इसे अपनाने में मदद मिल सके। यह पोर्टल खास डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्निकल रिसोर्स तक पहुंच देता है। यह

भारत के अनुभव और दोस्त देशों की ज़रूरतों के बीच एक पुल का काम करता है। इस पहल के ज़रिए, डिजिटल पब्लिक गुड्स को फिक्स्ड टेम्पलेट के बजाय एडैप्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर दिखाया जाता है।

## जी20 डिक्लेरेशन और ग्लोबल डीपीआई रिपोर्टिरी

---

2023 में अपनी जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट एजेंडा के सेंटर में रखा। जी20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ने डीपीआई को एक डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर के तौर पर साफ़ तौर पर मान्यता दी। भारत ने यह आइडिया दिया कि डीपीआई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इनक्लूसिव ग्रोथ के लिए डिजिटल रेल है, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिरी को भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत सबक और प्रैक्टिस शेयर करने के लिए एक नॉलेज प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च किया गया था। इसे पॉपुलेशन स्केल डीपीआई को डिज़ाइन करने और डिप्लॉय करने के बारे में जानकारी के गैप को भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत ने रिपोर्टिरी में सबसे ज़्यादा DPI सॉल्यूशन दिए, जिससे बातचीत को आकार देने में इसकी भूमिका मज़बूत हुई।

## कोविन एक ओपन डिजिटल पब्लिक गुड के तौर पर

---

भारत ने कोविन को दुनिया को बिना किसी कीमत के ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर देकर अपने डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को देश की सीमाओं से आगे बढ़ाया है। 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज़ को मैनेज करने में प्लेटफॉर्म की सफलता ने बड़े पैमाने पर मुश्किल पब्लिक हेल्थ लॉजिस्टिक्स को कोऑर्डिनेट करने की क्षमता दिखाई है। टेक्नोलॉजी को फ्री में उपलब्ध कराकर, भारत ने संकेत दिया कि उसका डिजिटल अनुभव शेयर करने के लिए है। पब्लिक गुड, इनक्लूसिव डेवलपमेंट और सोशल एम्पावरमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और पॉलिसी का इसका इस्तेमाल, उन विकासशील देशों के लिए प्रैक्टिकल सबक देता है जो मज़बूत डिजिटल सिस्टम चाहते हैं।

## MOSIP और सॉवरेन डिजिटल आइडेंटिटी

---

भारत में बनाया गया मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (MOSIP) एक और ज़रूरी उदाहरण है। MOSIP उन देशों के लिए एक कॉन्फ़िगर करने लायक और ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क देता है जो

सॉबरेन डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाना चाहते हैं। 25 से ज़्यादा देश अपने नेशनल आइडेंटिटी प्रोग्राम के लिए इस प्लेटफॉर्म को अपना रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं। कुल मिलाकर, ये कोशिशें एक ऐसी डिप्लोमेसी को दिखाती हैं जो शेयर्ड कैपेबिलिटी पर आधारित है, जहाँ भारत एक ज़्यादा इनक्लूसिव और इंटरऑपरेबल ग्लोबल डिजिटल आर्किटेक्चर को बनाने में मदद कर रहा है।

## निष्कर्ष

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की अवधारणा में आए व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ यह सफर अब एक व्यापक, अंतरसंचालनीय संरचना में परिणत हो चुका है जो आर्थिक गतिविधियों, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता का आधार है। यह मॉडल दर्शाता है कि व्यापकता से विश्वास पर कोई समझौता नहीं होता, और पारदर्शिता सुरक्षा और विनियमन के साथ-साथ चल सकती है। प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक उद्देश्य से जोड़कर, भारत ने यह दिखाया है कि डिजिटल प्रणालियाँ विकास को गति देते हुए लोकतंत्र को मजबूत कर सकती हैं। जैसे-जैसे अधिक राष्ट्र लचीले और समावेशी डिजिटल आधार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत का अनुभव न केवल एक केस स्टडी के रूप में, बल्कि सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के भविष्य के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में भी सामने आता है।

## संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय:

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224505&reg=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2124910&reg=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1626979&reg=3&lang=2>
- <https://www.poshantracker.in/>

संचार मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2206477&reg=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223772&reg=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225881&reg=3&lang=2>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- <https://ncd.mohfw.gov.in/>

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225805&reg=3&lang=2>
- [https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2721\\_jFgCof.pdf?source=pqals](https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2721_jFgCof.pdf?source=pqals)

विधि एवं न्याय मंत्रालय:

- <https://www.pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=2085127&reg=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223647&reg=3&lang=1>

### यूएनडीपी

- <https://www.undp.org/digital/digital-public-infrastructure>

### विदेश मंत्रालय

- [https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/39020/Opening\\_Address\\_by\\_Prime\\_Minister\\_Shri\\_Narendra\\_Modi\\_at\\_the\\_AI\\_Action\\_Summit\\_Paris\\_February\\_11\\_2025](https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/39020/Opening_Address_by_Prime_Minister_Shri_Narendra_Modi_at_the_AI_Action_Summit_Paris_February_11_2025)
- <https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/MY24B4504.pdf>

### पीएमओ

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225059&reg=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1772811&reg=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2176893&reg=3&lang=2>

### पीआईबी शोध

### पीके/केसी/एनएम